1. वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर और नगर संकुलता के दृष्टिगत, भारत के एक प्रमुख नगर के नगर प्रशासन ने अपने केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र में एक डायनामिक पेड पार्किंग नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति का उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और दुर्लभ नगरीय भूमि का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत, विशेष रूप से सर्वाधिक व्यस्त समय के दौरान पार्किंग शुल्क उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिए जाएंगे और डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ शुरू की जाएंगी। इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग सार्वजनिक परिवहन और पैदल यात्री अवसंरचना में सुधार के लिये प्रस्तावित है।

हालाँकि, इस नीति को लेकर स्थानीय व्यापार स्वामियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि उन्हें भय है कि ग्राहकों की संख्या कम हो जाएगी; दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और निम्न आय वर्ग, जो अपने दोपहिया वाहनों के लिये किफायती पार्किंग पर निर्भर हैं, का तर्क है कि यह नीति प्रतिगामी है; पर्यावरण समूह और नगर योजनाकारों ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और संधारणीय आवागमन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए इस निर्णय का समर्थन किया है।

राजस्व उपयोग की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार या उत्पीड़न के बिना नई प्रणाली का क्रियान्वन करने की नगरपालिका प्रशासन की क्षमता को लेकर भी चिंताएँ है। (250 शब्द) 20

आप वह नगरपालिका आयुक्त हैं जिसका उत्तरदायित्व इस नीति का क्रियान्वन करना है।

In response to rising air pollution and urban congestion, the municipal government of a major Indian city has decided to implement a dynamic paid parking policy in its central business district. The policy aims to discourage private vehicle use, promote public transport, and ensure efficient use of scarce urban land. Under this policy, parking fees will be significantly increased, especially during peak hours, and digital payment systems will be introduced. The revenue generated is proposed to be used for improving public transport and pedestrian infrastructure.

However, the policy has triggered strong reactions from Local business owners fear reduced customer footfall, Daily wage workers and lower-income groups, who rely on affordable parking for their two-wheelers, argue the policy is regressive, Environmental groups and urban planners support the move, citing global best practices and the need to prioritize sustainable mobility.

There are also concerns about the transparency of revenue utilization and the capacity of the municipal administration to enforce the new system without corruption or harassment. (250 words) 20

You are the Municipal Commissioner responsible for implementing this policy.

(a) विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करने में आपके निर्णयन में किन मूल्यों और सिद्धांतों का मार्गदर्शन होना चाहिये?
What values and principles should guide your decision-making in balancing the interests of different stakeholders?

(b) ऐसी कार्ययोजना का सुझाव दीजिये जिससे पारदर्शिता, समानता और प्रभावी नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित हो।
Suggest a course of action that ensures transparency, equity, and effective policy implementation.

(c) आप पार्किंग शुल्क से प्राप्त धन के संभावित भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की आशंकाओं का समाधान किस प्रकार करेंगे?
How would you address concerns of possible corruption and misuse of funds generated from parking fees?

उम्मीदवार हाशिये में चाहिये।
(Candida
write on

उपरोक्त केस स्टडी में आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण जैसे धारणीय विकास के मुद्दे तथा संविधान द्वारा प्रदत्त आजीविका का अधिकार (19(1)(g)) तथा DPSP में उल्लेखित राज्य के दायित्वों के बीच संबंधों को रेखांकित किया है।

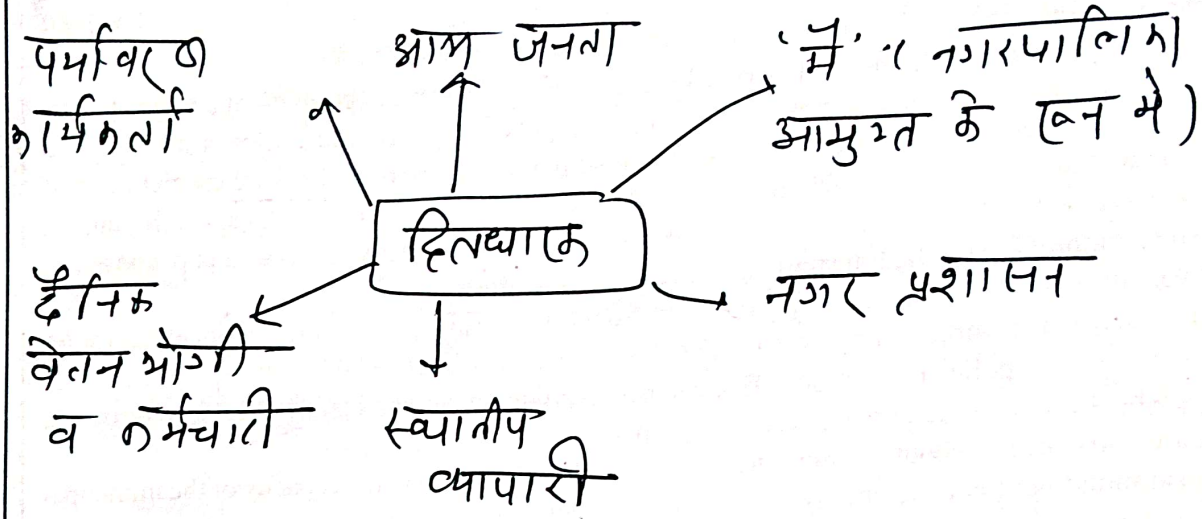

(a) विभिन्न हितधारकों के हितों के संतुलन हेतु मार्गदर्शक व सिद्धांत :-

↳ (1) धारणीय विकास :- आर्थिक विकास तथा पारिस्थितिकी के बीच संतुलन।

↳ (2) उपयोगितावाद — नीति से अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की अपेक्षा।

↳ (3) मानव केन्द्रित दृष्टिकोण (पूर्णतावाद) :- अंतिम हित मानव का जो कि पर्यावरण से सीधा संबंधित है।

हाशिये में न ... चाहिये। (Candidate ... write on th...

(4) अभिवृत्ति परिवर्तन / अनुनयन :- असंतुष्ट हितधारकों के लिए।

(5) भावनात्मक बुद्धिमत्ता :- विभिन्न हित धारकों के हितों के बीच संतुलन।

(6) निष्पक्षता / वस्तुनिष्ठता :- निष्पक्ष तथा तटस्थ होकर नीति निर्माण

(b) पारदर्शिता, समानता और प्रभावी नीति को सुनिश्चित करने वाले कार्ययोजना के आयाम :-

---

(1) पारदर्शिता :- नीति निर्माण में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाया जाए।
↳ सहभागितामूलक नीति निर्माण की प्रक्रिया का सहारा लें।
↳ ~~सूचना के~~ RTI 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यान्वयन।

(2.) समानता → Cost benefit Analysis तथा EIA पर बल।
→ निर्णयन की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक किया जाए।
↳ समावेशी सिद्धांतों का अनुगमन।

(3.) प्रभावी नीति — सेवा भाव पर बल।
↳ दक्षतापूर्ण निर्णयन व कार्यान्वयन।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

↳ लोकसेवाओं के प्रति समर्पण की अनिवार्यता।

(c) प्राप्त धन के संभावित दुरुपयोग के समाधान हेतु कैसे उपाय। -

↳ (1.) पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित कोष को RTI 2005 के अंतर्गत लाऊंगा।

↳ (2.) धन के उपयोग तथा वितरण में डिजिटल साधनों का उपयोग (ई. गवर्नेंस)

↳ (3.) की नियमित अंकेक्षण जिसमें सामाजिक अंकेक्षण भी शामिल होगा का सहारा लेना।

↳ (4.) जिम्मेदार अधिकारियों के उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण

↳ (5.) मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण।

↳ (6) नियमित निगरानी तथा शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था।

ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सर्वोत्तम मॉडल का अनुगमन तथा सहभागिता एवं निर्णय एक उत्तम साधन होगा।